समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.04.2015

मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2015 को अध्ययन समूह (ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान) के अन्तर्गत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव/निदेशक, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 डा0 रुद्र प्रताप द्वारा मा0 श्री निहाल अजमत चौधरी, सदस्य राज्य योजना आयोग का हार्दिक स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। निदेशक, पशुपालन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गठित इस अध्ययन समूह के स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। उनके द्वारा विभाग द्वारा संचालित कुक्कुट विकास नीति–2013, प्रजनन नीति, नेशनल लाइव स्टाक मिशन, 19वीं पशुगणना– 2012, कामधेनु योजना एवं विभाग में कार्यरत संस्थाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। राज्य योजना आयोग द्वारा अध्ययन समूह हेतु चयनित निम्न बिन्दुओं पर वृहद चर्चा की गयी :–

1. पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिये सम्भावनाओं का पता लगाना।

2. पशुपालको को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराना।

3. पशुओ के स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना।

- निदेशक, पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 2200 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 'द' श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय एवं 6 पॉलीक्लीनिक स्थापित है, जिनके माध्यम से पशुचिकित्साविदों द्वारा पशुपालकों को सीधे पशु चिकित्सा सेवायें दी जा रही है परन्तु पशुओं की संख्या को देखा जाय तो उसके अनुपात में सुविधायें अपर्याप्त है। अतः नवसृजित पशुचिकित्सालयों एवं पशुचिकित्साविदों के पदों का सृजन किया जाना अति आवश्यक है, जिससे पशुपालको को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके। मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग द्वारा इस बिन्दु पर सहमति प्रदान की गयी।

- निदेशक, पशुपालन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 47 मोबाईल वेटनरी क्लीनिक की स्थापना की गयी है, शेष विभिन्न जनपदों में 4 मोबाईल क्लीनिक क्रियाशील हैं जिसके द्वारा पशुपालकों के द्वार पर समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। जिसका लाभ सीधे पशुपालकों को मिल रहा है। इसी प्रकार प्रदेश के सभी ब्लाकों पर भी मोबाईल वेटनरी क्लीनिक की स्थापना की जा सकती है। पशुपालकों के पशुओं को त्वरित स्वास्थ्य सेवायें एवं अन्य पशुपालन संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक मोबाईल वैन क्लीनिक हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। जिसपर मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

- बैठक में चर्चा हुई की पशुपालक अधिक से अधिक पशुपालन हेतु प्रेरित हो व क्षेत्र में उद्यमिता का विकास हो इसके लिए पशुपालकों को पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हुए क्षमता की वृद्धि की जानी चाहिए इसके लिए त्रिस्तरीय प्रयास किये जाने होगें। प्रथम स्तर पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता/संसाधन मुहैया कराये जाना, विभाग के कार्यक्रमों एवं उनके आच्छादन के गैपस को पूरा किया जाना एवं पशुधन एवं पशुजन उत्पादों के विपणन की प्रभावी व्यवस्था उचित दरों पर सृजित किया जाना आवश्यक होगा। इन तीनों क्षेत्रों में सार्थक एवं समेकित प्रयास से पशुपालन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति होगीं, पशुपालक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर होगा।

- विस्तारित चर्चा में उन्होंने बताया कि पशुपालको के उत्पादों (दूध, अण्डा, मॉस) का उचित मूल्य सगठित बाजार क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी न होने के कारण प्राप्त नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में पशुपालक, आधुनिक तरीके से पशुपालन एवं डेयरी कार्यो में रूची नही ले रहा है। जिसके समाधान हेतु कार्य योजना में विचार किया जा सकता है।

- बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के लिये मोबाईल वेटनरी क्लीनिक/टू वृहलर वाहन की आवश्यकता है, जिससे कि पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान किया जा सके।

- पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह समय से प्राप्त हो सके। आधुनिक आई0टी0 के समावेश पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे ब्लाक, के0वी0के0, कृषि/पशुचिकित्सा विश्व विद्यालयों एवं भारत सरकार की संस्थाओं से समन्वय की भी चर्चा हुई।

- संयुक्त दुग्ध आयुक्त, डेयरी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डेयरी विभाग द्वारा पशुपालकों से प्राप्त दुग्ध का उचित मूल्य के भुगतान में अन्य प्रदेशों की सरकारों द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। इसके लिये कार्य योजना बनाकर सब्सिडी का प्राविधान कराया जा सकता है। जिससे अधिक दूध का संग्रह हो सके। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि बजट के आभाव में प्राईवेट दुग्ध संग्रह संस्थाओं के तुलना में पशुपालकों को कम सुविधाये दी जा रही है। पशुपालन विभाग द्वारा कामधेनु योजनान्र्तगत उत्पादित दूध को संग्रहित करने हेतु उन पशुपालको को डेयरी विभाग से जोड़ा जाये यदि आवश्यकता हो तो उन ईकाइयों में बी0एम0सी0 की स्थापना हेतु कार्ययोजना बनाई जा सकती है।

- श्री पी0एस0ओझा, राज्य संयोजक बी0ई0एम0सी0 नियोजन विभाग द्वारा उक्त चर्चा में प्रतिभाग करते हुये राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 पर विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कामधेनु योजना के अर्न्तगत ईकाइयों द्वारा उत्पादित गोबर का समुचित प्रयोग हेतु परियोजना से डबटेल कर बायोगैस उत्पादों का संचालन करने में सहयोग हेतु बल दिया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सामान्य चारागाह, कृषि एवं सामाजिक वानिकी हेतु उपयुक्त भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर बायो इनर्जी क्राप्स का रोपण मिनी डेयरी/वृहद डेयरी की परियोजनाओं से डबटेल कर बायोगैस उत्पादों का संचालन किया जा सकता है।

बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी एवं निम्न निर्णय लिये गयेः–

- मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि इस अध्ययन समूह के अर्न्तगत एक तकनीकी उप समिति का गठन किया जाये जो पशुपालन के क्षेत्र में उभरे हुये बिन्दुओं पर कार्ययोजना बनाकर अध्ययन समूह के समक्ष प्रस्तुत करे। डेयरी विभाग एवं बी0ई0एम0सी0 नियोजन विभाग अपने से संम्बधी बिन्दु पर कार्य योजना प्रस्तुत करे।

अन्त में समूह के संयोजक श्री निहाल अजमत चौधरी, सदस्य, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बैठक की चर्चा को समग्र रूप से लेते हुए यह विचार रखा गया कि यह बैठक इस क्षेत्र में प्रारम्भिक विश्लेषण एवं गैपस को चिन्हित करने में सहायक सिद्ध हुई। इन्हीं बिन्दुओं पर आगे कार्ययोजना एवं संस्तुति निर्भर रहेगी जिनपर समयबद्ध रूप से अगली बैठकों में निर्णय किया जा सकेगा। उक्त अध्ययन समूह के सदस्य सचिव/निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा अध्यक्ष की सहमति से समूह की अगली बैठक दिंनाक 07.05.2015 एवं दिनांक 15.05. 2015 को निर्धारित की गयी है। उक्त निर्णय के साथ ही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।